भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1621
उत्तर देने की तारीख 13 दिसम्बर, 2023

दूरस्थ गांवों में मोबाइल सेवाएं

1621. श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के दूरस्थ गांवों में मोबाइल सेवाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) मध्य प्रदेश विशेषकर ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में मोबाइल सेवाओं से वंचित गांवों की कुल संख्या कितनी है; और
(ग) उक्त गांवों में मोबाइल नेटवर्क सेवाओं का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ग) पिछले 10 वर्षों में देश में दूरसंचार कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) की कुल संख्या मार्च-2014 में 6.49 लाख से बढ़कर मार्च-2023 में 25.42 लाख हो गई है। कुल मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2014 में 90.45 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2023 में 114.84 करोड़ हो गई हैं। उपभोक्ताओं की संख्या मार्च-2014 में इंटरनेट 25.15 करोड़ से बढ़कर मार्च-2023 में 88.12 करोड़ हो गई है।

सितंबर 2023 तक देश के 6,44,131 गांवों (भारत के महारजिस्ट्रार के अनुसार गांव के आंकड़े) में से लगभग 6,16,300 गांवों में 95.7% कवरेज के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में 55,058 गांवों में से 53,119 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान कर दी गई है जिसमें ग्वालियर और शिवपुरी जिलों के 1,852 गांव शामिल हैं।

पूरे भारत में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारतनेट परियोजना ने 2.07 लाख गांवों को जोड़ा है। हाल ही में इसके दायरे को 1.88 लाख करोड़ रुपये कुल परिव्यय पर सभी बसे हुए गांवों को सेवा प्रदान करने के लिए बढ़ाया गया है। दिनांक 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग स्थानों सहित 7,535 गांवों को कवर करते हुए 6,394 मोबाइल टावर पहले ही चालू किए जा चुके हैं।

देश के दूरसंचार सेवा से वंचित गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार ने कई स्कीमें शुरू की हैं। सरकार ने 41,331 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 54,000 से अधिक गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देश के सेवा से वंचित क्षेत्रों में 41,160 टावरों की योजना बनाई है।

*****